RELEASE OF >Srmi RANAHE FROM LISBON JAIL

169. PROF. SATYAVRATA SIDDHANTALANKAR: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the mother of Shri Ranade or her representative Shri Dandekar wanted to meet the U. N. Secretary-General, U Thant, during his recent visit to this country, to request him to move in the matter of release of Shri Ranade from the Lisbon Jail;

(b) if so, whether the said meeting could be arranged with the Secretary-General; and

(c) if the answer to part (b) above be in the affirmative what was the result of the meeting?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI M. C. CHAGLA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) It was not found possible to arrange this meeting on account of the tight schedule of the U. N. Secretary-General. Although a matter like this does not fall within the scope of the U. N. Secretary-General's functions, the Government of India did mention to the Secretary-General the incarceration and plight of Shri Mohan Laxman Ranade in the Portuguese jail. This is apart from the efforts the Government of India have been making and are making through other channels to secure Shri Ranade's release.

J403. [Transferred *to the* 16th *June,* 1967].

^Transferred from the 2nd June, 1967.

•{•Transferred from the 26th May, 1967].

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ACUTE SCARCITY AND FAMINE CONDITIONS IN A NUMBER OF DISTRICTS OF MADHYA PRADESH, ESPECIALLY IN SARGUJA AND VINDHYA REGIONS

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया (मध्य प्रदेश) : सभापति जी, आपके माध्यम से मैं मध्य प्रदेश के कई जिलों, विशेषकर सरगुजा और विन्ध्य क्षेत्रों में भारी कमी और अकाल की स्थिति की ओर खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

THE MINISTER OF FOOD AND* AGRICULTURE (SHRI J AG JI VAN RAM): Sir, several districts of Madhya Pradesh have been affected by drought Some of them are severely affected.

2. The State Government have started relief works. According to the latest reports received from the State Government 8,63,737 persons are engaged on 5,818 relief works. Persons too old and infirm to do hard manual labour and other deserving persons are being given gratuitous relief. The number of persons receiving gratuitous relief is 35,009 according to latest reports. Programmes for augmenting supply of drinking water and supplying drinking water through tankers and bullock carts have been taken up where necessary. The State Government have also made arrangements for supply of fodder free or at concessional rates.

3. Feeding programmes have *been* organised in cooperation with CARE and UNICEF. The scope of these pro grammes is being extended. CARE asked for a loan of 4000 tonnes of wheat for these programmes yester day and the Ministry of Food and Agriculture have already agreed to give this loan.

4. The Ministry of Food and Agri culture have allotted 3,000 tonnes of wheat, about 300 tonnes of milk

[Shri Jagjivan Ram.]

powder and 11 tonnes of dry raisins for free distribution in the drought affected areas of M.P. UNICEF have offered 700 tonnes of CSM (a high protein food) and about 430 tonnes of milkpowder for these programmes. The number of persons benefiting from these programmes is over 3 lakhs.

5. A sum of Rs. 16 icrores was advanced as loans and grants to the Madhya Pradesh Government for relief expenditure during 1966-67 besides short term !oans of Rs. 4:934 crores for purchase of inputs like seeds, fertilisers and pesticides. During 1967-68 short term loans of Rs. 0:675 crores have been sanctioned so far for purchase of inputs.

6. Some reports of starvation deaths in Madhya Pradesh have appeared in the newspapers. These have been sent to the State Government for investigation and report. The reports of the State Government are still awaited.

7. The State Government have been making efforts to procure foodgrains from within the .State to feed the people in the severely affected districts. In view of the poor availability of foodgrains with Government of India and because of the need to main-taia supplies to the severely affected States like Bihar and Uttar Pradesh and also to meet the minimal needs of other deficit States, it has not been possible to increase the allotments to Madhya Pradesh over the level of about 30.000 tonnes per month.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चोरड़िया : क्या श्रीमान् यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश की स्थिति में, आपके इतना सब करने के बाद भी, अभी कल परसों ही अखबार में ग्वालियर की राजमाता और विरोधी दल के नेता श्री सखलेजा के बारे में वक्तव्य आए थे, उनमें उन्होंने विरोध प्रकट किया था, तो लोगों से जानकारी लेने के बाद यह पता लगा है कि लगभग 150 आदमियों की मौतें हुई हैं और 6 जिले अकालग्रस्त घोषित किये हैं। आप खुद भी यह स्वीकार करते हैं—75 या ऐसे ही कुछ आपने बताया कि ऐसा सुना है कि इतनी मौतें हो गई—तो ऐसी स्थिति में यह तो निर्विवाद है कि हमारे अभी तक किये गये प्रयत्न अपर्याप्त हैं। तो क्या मंत्री जी यह बतलाएंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिये केन्द्रीय सरकार से क्या क्या स्पेसिफिक सहायता मांगी, उसमें से अभी तक कितनी कितनी दी जा चुकी है, कितनी कितनी के लिये इनकार किया जा चुका है, और कितनी कितनी दी जाने वाली है—यह बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री जगजीवन राम : इसका विवरण तो अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन एक दो बातें मैं कह देना चाहता हूं। जहां तक रिलीफ का प्रश्न है, रिलीफ आपरेशन के लिये जितनी भी रुपये की आवश्यकता मध्य प्रदेश को होगी, उसको देने में केन्द्र से कोताही नहीं की जायेगी और मेरा अपना अंदाज है कि अब काम वहां तेजी पकड़ रहा है, काम और भी ज्यादा हो रहा है। जैसा कि मैंने अभी कहा है, लोगों को भोजन देने का काम, काम में लगाने का काम, यह सब कई एक संस्थाओं की मार्फत और भी अधिक विस्तारपूर्वक चलने को है। जहां तक आपने मौत की बात कही, तो उसके संबंध में कोई भी निश्चित राय जाहिर करने की अवस्था में मैं नहीं हूं, जैसा कि मैंने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार के पास रिपोर्ट के लिये हमने भेजा है। उनसे रिपोर्ट आने के बाद ही मैं कुछ निश्चित बात बता सकूंगा।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चोरड़िया : One question more. । क्या श्रीमान् कम से कम मोटे रूप में यह तो बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने कितना अनाज मांगा था और वास्तव में केन्द्रीय सरकार ने उनको कितना दिया है ? यह निश्चित है कि जो उन्होंने मांग की थी उससे बहुत कम केन्द्रीय सरकार ने दिया और इसलिये मध्य प्रदेश सरकार की और भी नाजुक स्थिति हो रही है। इस समस्या को मीट आऊट करने के लिये क्या हमारी केन्द्रीय सरकार इस बात की प्रतीक्षा कर रही

है कि मध्य प्रदेश के भी संसद सदस्य मिलकर केन्द्रीय सरकार से या माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करें और उस तरीके को अपनाएं जिसको कि कुछ लोग अपना सकते हैं और फिर बाद में आप मजबूर होकर मध्य प्रदेश का कोटा बढ़ायें, अथवा आवश्यकतानुसार जितनी मांग की गई उतना देने को तैयार हैं ?

श्री जगजीवन राम : नहीं, जितनी मांग की गई है उतना नहीं दे पाए हैं, देने की सामर्थ्य ही नहीं रही है, और यह जो माननीय सदस्य के दिमाग में कोई बात हो कि कुछ संसद सदस्यों द्वारा कुछ कार्यवाही करने की वजह से कहीं का कोटा बढ़ गया हो तो यह भ्रम है। यह भ्रम की बात है। केवल ऐसा करने से कहीं कोटा बढ़ जाय तो इसके मानी हुए कि हमारे पास है लेकिन नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो स्थिति है उसके साथ पूरी सहानुभूति रखते हुए जो मैं अधिक से अधिक कर सकता हूं, करने के लिये प्रयत्न कर रहा हूं। लेकिन, जैसा कि मैंने बताया, आज केन्द्र की भी स्थिति ऐसी नहीं है कि जितने की आवश्यकता किसी प्रान्त को हो उसको हम पूरा कर पाये हों। सब प्रान्तों में शिकायत रही है कि जितनी उनकी मांग थी उतना नहीं दे पाये हैं। लेकिन जितना हमारे सामर्थ्य में है उतना अधिक से अधिक देने का प्रयत्न करते हैं और मध्य प्रदेश को भी हम देंगे। यह हम दावा नहीं करते हैं कि जितना उन्होंने मांगा है उतना हम दे पाए हैं। मैंने पहले ही कहा है।

श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) : क्या श्रीमान् यह बताने का कष्ट करेंगे कि मध्य प्रदेश में खाद्य स्थिति कमज़ोर है, यह श्रीमान् के मंत्रालय को कब पता लग और अगर आज से तीन महीने पहले पता चल गया था तो श्रीमान् के मंत्रालय ने, 5 लाख बोरे गुलाबी चना बाहर भेजने के लिये जो परमिट उन्होंने मांगा, उसको देने के लिये रोक क्यों नहीं लगाई। एक एक परमिट के पीछे दस दस से लेकर बीस बीस रुपए तक का भ्रष्टाचार हुआ। क्या श्रीमान् को इसकी जानकारी है और इसकी भी जानकारी है कि जिसके नाम परमिट जारी हुआ...

श्री जगजीवन राम : सदस्य महोदय बहुत से लांछन लगा रहे हैं। He is making certain allegations against the State Government.

श्री निरंजन वर्मा : ये केवल एलीगेशंस हैं ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। ये एलीगेशन्स भी हैं, तथ्य भी हैं।

SHRI JAGJIVAN RAM: These clarification, do not make allegations.

MR. CHAIRMAN: Please ask for clarification, do not make allegations.

SHRI JAGJIVAN RAM: This is not the proper forum to make such allegations.

श्री निरंजन वर्मा : मंत्री महोदय हमेशा एलीगेशन की बात कह कर मामले को भड़काना चाहते हैं। मैं क्लियर पूछ रहा हूँ कि आप बताने का कष्ट कीजिए कि आज से तीन महीना पहले क्या आपको ज्ञान नहीं था कि मध्य प्रदेश में भुखमरी की आशंका है, वहां पर पैदावार कम हो रही है, और अगर वहां पर यह बात थी तो आपने वहां से अनुमति क्यों दी, इसका आपके पास कोई उत्तर है ? दूसरी बात, मध्य प्रदेश सरकार ने आप से किन किन चीजों की मांग की ? आप से अन्न मांगा, आप से रुपया मांगा और उन्होंने अकाल को घोषित किये जाने की स्थिति के लिये आपके पास कोई रिपोर्ट भेजी है या नहीं भेजी है ? कृपा करके इन बातों को बतलाइये।

श्री जगजीवन राम : जी हां। दो महीने पहले मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह जिक्र जरूर किया था कि उनके यहां इस साल पैदावार कुछ सालों की अपेक्षा कम होगी, तो क्या केन्द्र इस साल कुछ सहायता देगी ?

श्री निरंजन वर्मा : सुनाई नहीं दे रहा है क्यों कि आप धीमे स्वर से बोल रहे हैं ।

श्री जगजीवन राम : अगर आप बीच में न बोलें तो सुनाई देगा ।

श्री निरंजन वर्मा : क्या आप समझते हैं कि बुद्धिमान आप ही हैं और दूसरे को बोलना नहीं आता है ।

श्री जगजीवन राम : मैं तो आपको बतला रहा हूं और अगर आप सुनने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो मैं क्या करूं ।

श्री निरंजन वर्मा : मतलब की बात जरा धीरे बोला करते हैं ।

MR. CHAIRMAN: The Minister is as anxious as you are to give the information. Kindly have patience and try to hear him.

श्री जगजीवन राम : आप धैर्य रखकर सुनें कि मैं क्या कह रहा हूं और मध्य प्रदेश शासन के ऊपर लांछन लगाने का प्रयत्न न करें । इस तरह से आप सभी बात सुन पायेंगे और मैं आपकी सभी बातों का जवाब दे सकूंगा । तो मैं बतला रहा था कि आज से दो महीने पहले, जब मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने मुझ से कहा कि हमारे प्रदेश में इस साल पहले सालों की तरह खाद्य स्थिति नहीं है । पहले मध्य प्रदेश अपने यहां जो अनाज पैदा करता था उसको अपने यहां ही रखता था और दूसरे प्रदशों को भी भेजता था । तो मैंने कहा कि यह सब स्थिति मुझे मालूम है, लेकिन मेरी भी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं बहुत अधिक सहायता कर सकूं । मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के जिस हिस्से में कुछ पैदावार हुई है वहां से कुछ अनाज उपलब्ध करके जिन इलाकों में कमी है, वहां पर भेजने का प्रयत्न किया जाना चाहिये । मैं तो जितना सम्भव होगा आपकी मदद करने का यत्न करूंगा ।

जहां तक चने का सवाल है, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है । लेकिन इतना जरूर सुना है कि वहां से चना कुछ बाहर भेजा गया है । लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां चना होता है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां चना बिल्कुल नहीं होता है । जिन इलाकों में चना नहीं होता है उन इलाकों में चना भेजा जाता है । इस साल चने का उत्पादन कम हुआ है, लेकिन फिर भी जिन जिन प्रदेशों में चना हुआ है वहां से कमी वाले इलाकों में चना भेजा गया है । आन्ध्र प्रदेश और मद्रास को भी यहां से चना भेजा जाता है ।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (मध्य प्रदेश) : मेरे तीन प्रश्न हैं और मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री जी उनका सही उत्तर देंगे । पहला यह है कि मार्च के महीने से जो 15,000 मे० टन प्रतिमास गेहूं का कोटा था वह घटाकर 13,000 मे० टन कर दिया गया । इतना होते हुए भी वास्तव में मार्च, अप्रैल और मई महीनों में इस कोटे में से 20,350 मे० टन गेहूं प्राप्त नहीं हुआ है । तो मैं यह जानना चाहती हूं कि यह अप्राप्त शेष कोटा जल्द से जल्द दिया जायगा ।

दूसरा प्रश्न यह है कि मार्च, अप्रैल और मई महीने में मीलों का कुछ कोटा एलाटमेंट 49,000 मे० टन हुआ था, परन्तु इस में से 30,560 मे० टन मीलों अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । इसलिए क्या मेहरबानी करके उसे देने का कष्ट करेंग ?

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि म० प्र० के 43 जिलों में से 38 जिले सूखाग्रस्त हैं और इनमें से 12 जिलों की हालत तो बिल्कुल खराब है । इसमें से विन्ध्य प्रदेश, सरगूजा और बहुत से 12 जिले हैं, जिनकी हालत बहुत नाजुक है । तो मेरी प्रार्थना यह है कि वहां पर दूसरे तरह के कार्य खुलवाकर उत्पीड़ित जनता को अन्न की सहायता

देकर वहा पर जो भूखमरी की आंशका है उसको बचाया जा सकता है। अभी वहां पर भूख से किसी की मौत हुई है, ऐसी मेरी जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे आशंका है कि अगर सावधानी के साथ कदम नहीं उठाया गया, तो वहां पर इस तरह की दुर्घटना हो सकती है।

श्री जगजीवन राम : जो कुछ मैंने बतलाया कि इतने लोगों को खिलाने का प्रबन्ध, इतने लोगों को दूध बांटने का काम केयर के हाथ में है। सरगूजा और वैसे जो उत्पीड़ित इलाके हैं वहां से यह काम आरम्भ किया गया है। मैं यह मानता हूं कि इस काम को विस्तार करने की आवश्यकता है और इसके लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी बतलाया कि केन्द्र से तीन हजार टन गहूं मुफ्त बांटने के लिए भेजा गया है और 4 हजार टन हम केयर को दे रहे हैं ताकि वह मुफ्त में लोगों को भोजन करवाये। जितना हमने मध्य प्रदेश को एक महीने के लिए अलाट किया था उतना हम नहीं भेज सके हैं और हम

SHRI NAND KISHORE BHATT (Madhya Pradesh): Sir, Madhya Pradesh has been a surplus State and it has always been trying to give food to our neighbouring States. But this time we are passing through a very unprecedented situation. May I request the hon. Minister that the quota which has been allotted to Madhya Pradesh should be restored in view of the very difficult position that has been obtaining there during the last three months?

SHRI J AG JI VAN RAM: We are continuing the quota. There has been at the moment a shortfall in the despatches. But as I have assured the hon. Members the quota will continue as before and efforts will be made to see that the full allotment is despatched to Madhya Pradesh.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat): Sir, I would like to know from the hon. Food Minister how far the charge of step-motherly treatment to the State of Madhya Pradesh is justified because these charges have been made publicly in many newspapers. May I know, Sir, whether the Ministry of Food is not treating the case of Madhya Pradesh as sympathetically as it should? Madhya Pradesh, we know, has always been surplus State. What is the reason that this situation has arisen there?

SHRI JAGJIVAN RAM: As I said, Sir, last year also the production suffered and this year also it has suffered. It has not so far so severely suffered as have Bihar and certain areai of U.P. The Madhya Pradesh Government has been very active. I say that it should be an example for other deficit areas also. They have undertaken a very active programme of procurement from the areas which have been comparatively better in production to procure from surplus areas and to send it to deficit areas, and we have also been helping to the best of our ability. There is no question of step-motherly treatment. *U* we have not been able to send as much quantities of foodgrains as are required by the State Government, the hon. Member is aware, we have not been able to do so in the case of any State. That is because of lack of availability. We have not met the food demand in any State, whether it is Gujarat or Maharashtra or any other State. \s I have said, in the drought-affected areas of M. P. free kitchen programme with the assistance of voluntary organisations as also a feeding programme for school children, nursing mothers, old ladies, infirm persons has been undertaken. And, as we have assured the House, the intention is very quikly to expand this programme to meet this contingency.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa): Sir, the people of certain districts in Madhya Pradesh are almost panicky, and I am told that people in hundreds, if not in thousands, are moving away from these districts of Sarguja and others adjoining towards Palamau in

[Shri Lokanath Misra.]

Bihar and some districts in Orissa. May I know, Sir, what effort is being made by the Government of India or the Madhya Pradesh Government to give confidence to these people who are in a state of panick not to move away, leaving their homes, from the State of Madhya Pradesh in distressed condition. Can I suggest one thinf? If the hon. Minister could kindly pay a visit to these areas, probably it would inspire confidence in the people to some extent. Is there any possibility of his visit to Madhya Pradesh in the near future? What other steps does he propose to take to inspire confidence in the people so that they do not go away from their homes 'eaving their houses?

SHRI JAGJIVAN RAM: As a matter of fact, the Prime Minister is going to that area, and I think the visit of the Prime Minister . . .

SHRI LOKANATH MISRA: You must go.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Do you think, Sir, the Foci Minister is relevant?

SHRI JAGJIVAN RAM: Of course, in answer to the question put by the hon. Member whether the Food Minister would go, I am saying that the Prime Minister herself is going to that area, and I personally ifeel that the visit of the Prime Minister will be certainly more effective. So far as the movement of the people from that area is concerned, whenever there is distress in any particular area, slight movement of population does take place. It becomes a matter of grave concern when the entire family moves. I have known it from personal experience and the hon. Member also knows that whenever there is distress in a particular area, peop'e from that area move out to find employment or better opportunities. That has to be there to some extent and I can say that so long as the relief measures were not started on a large scale in Sarguja area and they were operating in Daltangan], a certain number of people did go to Palamao district from Sarguja and also from Mirzapur And some people from Bihar went to Mirzapur area also, happens. But there has been no large-scale movement, and with all the in. ;u sures that the Madhya Pradesh Government has taken and with, of course, whatever assistance that we can extend to them in matters of supplying finances to them, I think the distress La the area will be re^eved.

SHRI S. S. MARISWAMY (Madras); Sir, the hon. Minister just now said that instead of him, the Prime Minister is going to Madhya Pradesh. Si;, the people of Madhya Pradesh, as my hon. friend, Shri Lokanath Misra, put it, are panicky. They would not derive much confidence by the visit of the Prime Minister for the simple reason that if they look at her, they may think that the whole of India is famine-stricken. But if our hon. Food Minister goes, they would derive much confidence and feel that at least Delhi is not famine-stricken and that food would come to them.

SHRI BHUPINDER SINGH (Punjab): May I know from the hon. Minister whether it is a fact that foodgrains are being supplied from various headquarters in Madhya Pradesh to various distribution centres for the people in scarcity-affected areas? It *is* reported that food supplies disappear on the way from the headquarters to the distribution centres in transit. What measures have Government taken to ensure that supplies sent by them to the distribution centres reach such centres intact to tact and are not misappropriated on the way? That is my first question. The second question is that in Narendragarh, District Sarguja, some organisations are running reMef camps. It is reported that people from surrounding areas are pouring into Narendragarh and they leave their children at the relief camps and then go away. These children are in very poor health. May I know

whether these reports are correct and what steps Government have taken to look after these children?

SHRI JAGJIVAN RAM: On the face of it, the first report does not appear to be correct or as having any foundation. The suggestion that the foodgrains moved from the district headquarters will disappear completely on the way without reaching the destination, I think, will not be accepted by any sensible person.

SHRI BHUPINDER SINGH: Nevertheless it happens.

SHRI JAGJIVAN RAM: I have *no* information on the specific question that you have put. I have no information about the relief camps that are being run at Narendragarh and for what they are meant.

डा० श्रीमती मंगलादेवी तलवार (राजस्थान): क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि मध्य प्रदेश को अब तक 15,000 मे० टन गहूं और 15,000 मे० टन मीलो प्रतिमास मिलता रहा है। इसके अतिरिक्त 5,000 मे० टन विदेशी गहूं प्रतिमास रोलर मैदा मिल के लिए, जिस पर बेकारी आदि आधारित है, मिलता था। परन्तु मार्च मास से यह 5,000 मे० टन विदेशी गेहूं का कोटा बन्द कर दिया गया है जिससे 449 बेकरियों के और रोलर मिल्स के बन्द हो जाने और परिणामस्वरूप हजारों लोगों के बेकार हो जाने की आशंका है। इसलिए विदेशी गेहूं का कोटा फिर से चालू किया जावे।

SHRI JAGJIVAN RAM: It is a request for action, but I will look into the question of what exactly is the prob'em of the bakeries.

SHRI R. S. KHANDEKAR (Madhya Pradesh): The hon. Minister said that the Prime Minister is going to visit the scarcity-affected areas. But so far neither a State Minister nor the Chief Minister nor the Deputy Minister nor the Central Food Minister has gone to the drought-affected areas. Secondly, the Madhya Pradesh Government has recently removed the inter-district ban on foodgrains. It is a welcome step, but at the same time, they have declared that they will close all the lair price shops from the 16th of June. Consequently, when the ban is removed, the prices will go up and the lower middle-class and the poor sections will be affected all the more if the fair-price shops are also closed as a result of the Central Government's not providing them with the adequate quota. May I get an assurance from the hon. Minister that the Central quota will be given to them as usual and the fair-price shops will be enabled to continue so that the poorer sections may not be affected? The hon. Minister also said that work is being provided to the people there. But what sort of work is there? They are asked to dig and repair roads and so on which they cannot do because of their weakness and because of their hunger. So why other work is not being provided to them? Lastly, there are complaints that they are not paid wages for weeks together. Will the Minister look into all these things and provide relief to those poor people?

SHRI JAGJIVAN RAM: I will take the last question first. So far as hard manual labour is concerned, I will draw the attention of the Madhya Pradesh Government that jf there has been any delay in the payment of wages to them, it should be regularly paid. Also in case they are very weak and not able to complete the work as detailed, a minimum daily wage should be ensured to them. So far as the Central allocation is concerned, Sir, I may assure the House, as I have said already, that we will continue- the monthly quota as at present.

SHRI R. S. KHANDEKAR: The fair price shops should be continued.

SHRI JAGJIVAN RAM: As regards the removal of restrictions on the inter-district movement of foodgrains in Madhya Pradesh, I know there was

[Shri Jagjivan Ram.]

a great demand from the public and members of that area for the removal of that restriction. They have removed that restriction in Madhya Pradesh and I think hon, Members will welcome that step. And as I have said, it will be for the Madhya Pradesh Government to decide, with the foodgrains that we supply and with the foodgrains that they have procured, what should be the best method for distribution among the vulnerable sections of the society.

SHRI D. L. SEN GUPTA (West Bengal): Mr. Chairman, Sir, you are fully aware that on the 31st May, I gave a Calling-Attention Motion in respect of West Bengal. To-day is the seventh day and yet the hon. Minister has not found it convenient to tell me when he will be in a position *to* answer that Calling-Attention. Sir, subject to that, I now put my questions. Let him fix some day, tomorrow or the day-after-tomorrow, for the Calling Attention . . .

MR. CHAIRMAN: That is a different matter.

SHRI D. L. SEN GUPTA: In the meantime, let me put these questions. I know this is in respect of Madhya Pradesh and I have full sympathy and the same feelings as other Members have in respect of Madhya Pradesh. But am I to understand that unless there is some sort of threat or pressure, this Government will not release either rice or wheat? They have succumbed to the threat of Kerala. They are going to succumb to the threat of Bihar and U. P. and also Madhya Pradesh. Am I to understand that after all rice and wheat are finished, then only the question of West Bengal will engage their attention?

SHRI JAGJIVAN RAM: Does it require an answer?

MR. CHAIRMAN: No. You have called the attention.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन, मुझे माननीय मंत्री जी का ध्यान खींचना है उस जवाब की ओर जो 20 मार्च को राज्य सभा में दिया गया था। माननीय मंत्री जी ने यह कह दिया बहुत ही आसानी से कि गुलाबी चने के बारे में मेरी जानकारी नहीं है कि किसको क्या दिया गया। 20 मार्च को इसी राज्य सभा में मध्य प्रदेश के गुलाबी चने के बारे में जवाब दिया है सरकार की ओर से। इस जवाब में माननीय मंत्री जी यह देखेंगे कि 276 इंडी-वीजुअल्स को 3,75,178.01 क्विन्टल और स्टेट कोआपरटिव माकरटिंग फडरेशन ईदगाह, भोपाल को 76,914 क्विन्टल-टोटल हुआ 4,52,092.01 क्विन्टल, यह सरकार ने लोगों को मध्य प्रदेश से गुलाबी चना बाहर भेजने के लिए परमिट दिया और यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरगुजा हम से लगा हुआ है और भुखमरी मिर्जापुर, बनारस की नौगढ़, रीवां और सरगुजा, सब जगह व्याप्त है। मैं बहुत ही अदब के साथ जानना चाहता हूं कि मर्च के महीने में या उसके पहले ही खाद्य स्थिति क्या है इसकी जानकारी सरकार को हो रही थी, सरकार जानती थी, मार्च में सरकार का यह उत्तर है। फिर सरकार मध्य प्रदेश के बारे में जिम्मेदारी लेने से क्यों बचती है और क्यों कहती है कि राज्य सरकार के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है ? राज्य सरकार के ऊपर लांछन लगाने का कोई मकसद नहीं है। राज्य सरकार ने चुनाव के दिनों में नाजायज तरीके से पैसा कमाने के लिए विभिन्न लोगों को परमिट दिए और एक-एक क्विन्टल के पीछे दस-दस रुपए उन लोगों से वसूल किया गया है जिनकी जानकारी कहीं कहीं 20-20 है। चुनाव के दिनों में जब म मध्य प्रदेश के दौर पर था, तो इसके बारे में मैंने कई बार राज्य सरकार को बताया। उस समय राज्य सरकार के मंत्री हमारे मित्र थे, कुछ समय हमारी पार्टी के सदस्य रह चुके थे, पार्टी में हम से जूनियर थे।

इसलिए म माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा अदब के साथ कि इवेजिस आन्सर न दें, मध्य प्रदेश पर जो खाद्य सकंट के बादल हैं उनकों इफेक्टिव तरीके से केन्द्र सरकार अपना कर्त्तव्य समझ कर दूर करे और कर्त्तव्य समझ कर राज्य सरकार को समुचित तरीके से कर्त्तव्य पालन की हिदायत करे। आज भी मध्य प्रदेश में बंगलिग हो रही है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कारण क्या है कि जितना इलाका, उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, मिर्जापुर, पलामू, सरगुजा, रीवां वगैरह है उसमें जो अकाल की छाया है उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए केन्द्र अपनी तरफ से कुछ राज्यों को सहायता प्रदान नहीं करता।

SHRI M. N. KAUL: Half-an-hour is over.

श्री जगजीवन राम : प्रश्न तो वही उठ गया जिसके बारे में मैंने कहा था कि यह प्रश्न उठाया जाना चाहिए था मध्य प्रदेश की असेम्बली में, जहां पर वहां के मंत्री उत्तर दे सकते थे। दस-दस रुपए लिए, यह लाछंन नही कहलाता है, तो क्या कहलाता है, उनकी डिक्शनरी में उसका कुछ और अर्थ होगा।

श्री राजन राय्थ : मिश्र जी की सरकार के लिए सामान्य बात है।

श्री जगजीवन राम : जो जो अब सरकार में आए हैं उन सबके भी आवरण उतरते जा रहे हैं। मैं यह कह रहा था कि मिर्जापुर, सरगुजा, पलामू, आरा जिले के सूखाग्रस्त होने के कारण वहां के लोग आक्रन्त हैं और वहां की राज्य सरकार काफी प्रयत्नशील हैं, और जैसा मैंने कहा और बार-बार दोहराना चाहता हूं कि रिलीफ मेजर्स के लिए जितने भी धन की आवश्यकता राज्य सरकारों को होगी वह मुहैया करने में कभी भी केन्द्र कोताही नहीं करेगा।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (196S-66) OF THE INDIAN RARE EARTHS LIMITED AND RELATED PAFERS

THE DEPUTY MINISTER (DR. SHRIMATi SAROJINI MAHISHI: On behalf of Shrimati Indira Gandhi I beg to lay on the Table, under subsection (1) of section 619-A of the Companies Act, 1956, a copy of the Annual Report and Accounts of the Indian Rare Earths Limited for the year 1965-66, together with the Auditors' Report on the Accounts. [Placed in Library. *See* No. LT-512/67].

REPORT OF THE DEARNESS ALLOWANCE COMMISSION

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT): I beg to lay on the Table a copy of the Report of the Dearness Allowance Commission o» the question of the grant of dearness allowances to Central Government employees in future. [Placed in Library. *See* No. LT-520/67].

I. ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (1965-66) OF THE GARDEN REACH WORKSHOPS LIMITED, CALCUTTA AND RELATED PAPERS

II. THE NAVY (DISCIPLINE AND MISCEL LANEOUS PROVISIONS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 1967

SHRI K. C. PANT: Sir, on behalf of Shri B. R. Bhagat, I also beg t« lay on the Table;

(a) A copy of the Annual Report and Accounts of the Garden Reach Workshops Limited, Calcutta, for the year 1965-66, together with the Auditors' Report on the Accounts, under sub-section (1) of section 619-A of the